

औरैया एवं कन्नौज में औद्योगिक विकास को दी जायेगी गति

- औरैया प्लास्टिक सिटी ने पकड़ी तेजी
- 500 से अधिक उद्यमी औरैया प्लास्टिक सिटी में निवेश को उत्सुक
- औरैया प्लास्टिक सिटी में 40,000 नवीन रोजगार के अवसरों का सृजन, कौशल विकास केन्द्र की होगी स्थापना
- कन्नौज में मक्का तथा आलू प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए दिलचस्पी
- कन्नौज के इत्र उद्योग को डियोडरेंट उद्योग से जोड़ने का सुझाव

लखनऊ 14 अगस्त, 2013:

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, डॉ० सूर्य प्रताप सिंह ने आज औद्योगिक विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करने तथा विकसित की जा रही परियोजनाओं का स्थल परीक्षण करने के लिए औरैया तथा कन्नौज का दौरा किया।

औरैया, दिबियापुर में विकसित की जा रही प्लास्टिक सिटी में देश के बड़े प्लास्टिक उद्योगपतियों ने गहरी रुचि दिखायी है। आल इण्डिया प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन (आइपमा) के चेयरमैन व सदस्यों ने आज औरैया में प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, डॉ० सूर्य प्रताप सिंह से इस परियोजना के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा विकास योजना के विषय में भेंट की, जिससे इसको समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जा सके। प्रमुख सचिव ने सम्बंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इस परियोजना को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करें अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, डॉ० सूर्य प्रताप सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी), मनोज सिंह तथा आइपमा के सदस्यों ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव, ने जिला मुख्यालय पर इस सम्बंध में एक समीक्षा बैठक की जिसमें जिलाधिकारी, औरैया एस. राजलिंगम, गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लि० (गेल) के अधिशासी निदेशक, एम. बी. गोहिल, आइपमा के चेयरमैन जयेश के. रामभिया, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज के कौशल पाण्डे तथा स्थानीय उद्यमियों सहित प्रशासनिक उच्चाधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, डॉ० सूर्य प्रताप सिंह ने कहा- "मा० मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि तथा सशक्त नेतृत्व के अन्तर्गत राज्य सरकार उद्यमियों तथा स्थानीय जनता के सहयोग से औरैया में प्लास्टिक सिटी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गेल की इकाई यहां पर पहले से ही स्थापित है जिससे प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध रहेगा, साथ ही यहां पर उच्च श्रेणी की अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा जिससे औरैया उत्तर भारत का एक बड़ा प्लास्टिक उत्पादन केन्द्र बन जायेगा।"

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध बड़े उपभोक्ता बाजार से प्लास्टिक उद्योग को परिवहन लागत में अच्छा लाभ होगा, क्योंकि वर्तमान में प्लास्टिक उत्पाद अन्य प्रदेशों से बनाकर यहाँ लाए जाते हैं।

प्लास्टिक उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की यह नई पहल है जिसके तहत यूपीएसआईडीसी गेल के साथ मिलकर इस रु०250 करोड़ की परियोजना का विकास कर रहा है। क्योंकि इस औद्योगिक परियोजना को सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) बनाकर विकसित किया जा रहा है अतः यूपीएसआईडीसी ने आइपमा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके अतिरिक्त गेल के साथ भी 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिससे कि कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति प्लास्टिक सिटी में की जा सके।

कुल 314 एकड़ भूमि में से 225 एकड़ भूमि पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जायेंगी जबकि शेष भूमि पर आवासीय भवन निर्मित किये जायेंगे। अभी तक यूपीएसआईडीसी ने रु०20 करोड़ की लागत से सड़कें, विद्युत वितरण लाइनें, सीवेज तथा ओवरहेड पानी की टंकी का निर्माण कर लिया है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक सिटी में वेयर हाउस, सीवेज शोधन संयंत्र, आवासीय टाउनशिप तथा गेल द्वारा कौशल विकास केन्द्र भी विकसित किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक यूपीएसआईडीसी मनोज सिंह ने बताया कि भारत सरकार से इस परियोजना हेतु रु०40 करोड़ की सहायता प्राप्त करने के लिए तथा सैद्धान्तिक सहमति व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आई.एल. एण्ड एफ.एस. को परियोजना विकास एजेन्सी के रूप में आबद्ध किया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 100 एकड़ भूमि को विकसित किया जायेगा तथा अभी तक पूरे देश से 523 उद्यमियों ने इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

प्लास्टिक सिटी में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एन.टी.पी.सी. की विद्यमान 600 मेगावाट के निकट ही 200 मेगावाट का संयंत्र स्थापित करने योजना है।

ज्ञात हो कि ईस्टर्न डेडिकेडेट फ्रेट कोरिडोर औरैया से होते हुए गुजरेगा तथा यहां पर एक नेशनल इनवेस्टमेंट मैनुफैक्चरिंग जोन भी प्रस्तावित है।

इसके बाद प्रमुख सचिव ने कन्नौज क्षेत्र का दौरा किया जहां पर वरदान ग्रुप ने एक मक्का प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई तथा एस. आई.सल्यूशन्स ने आलू प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त ही है।

रु0150 करोड़ के निवेश से मक्का प्रसंस्करण इकाई में मक्के का स्टार्च बनाया जायेगा जिसके लिए 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। रु0400 करोड़ के निवेश से 50 एकड़ क्षेत्रफल में आलू प्रसंस्करण इकाई का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

कन्नौज जिला मुख्यालय पर प्रमुख सचिव ने कन्नौज में औद्योगिक विकास की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की जिसमें वहां के जिलाधिकारी, डॉ0 रूपेश कुमार एवं स्थानीय उद्यमी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी कन्नौज ने आश्वासन दिया कि औद्योगिक विकास के लिए शीघ्र ही 70 एकड़ भूमि का प्रबन्ध किया जायेगा।

प्रमुख सचिव ने कन्नौज के परम्परागत इत्र उत्पादक का आवाहन किया कि वे बदलते जमाने में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार अपने उद्यम का विविधीकरण कर डियोडरेंट उद्योग से जुड़ने का प्रयास करें।

प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी मनोज सिंह ने कहा कि यूपीएसआईडीसी विशेष प्रयास करके कन्नौज में 250 एकड़ भूमि का प्रबन्ध कर उस पर औद्योगिक अवरस्थापना सुविधाएं विकसित करेगा।
